



NEWSLETTER

GOLD : 51950
SILVER : 58182
CRUD OIL : 8591

Download Our App "SIS CONNECT" For Daily Updates.

02/07/2022

जानिए देश में क्या है कॉटन सोइंग की वर्तमान स्थिति

टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इनदिनों का एक अहम मुद्दा है कॉटन सोइंग। क्योंकि इसी के आधार पर आने वाले साल का बिजनेस निर्भर करेगा। अप्रैल महीने के अंत से ही सोइंग आंकड़ों को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। पहले लगभग सभी प्रदेशों ने कॉटन सोइंग रकबा बढ़ाने की बात कही लेकिन जून खत्म होने तक स्थिति यह बनी कि रकबा बढ़ने की जगह घट गया। आइए जानते हैं वर्तमान में क्या है देश में कॉटन सोइंग की स्थिति-

COTTON SOWING as on 01/07/2022				
(Lakh Hectare)	SMART INFO SERVICES CALL : 91119 77775			
STATE	2022-2023	2021-2022	ONE YEAR CHANGE	CHANGE %
PUNJAB	2.480	2.541	-0.061	-2.40
HARYANA	6.505	6.745	-0.240	-3.56
RAJASTHAN	5.565	5.365	0.200	3.73
NORTH ZONE	14.550	14.651	-0.101	-0.69
GUJARAT	10.859	11.461	-0.602	-5.25
MAHARASHTRA	23.647	19.586	4.061	20.73
MADHYA PRADESH	1.800	3.340	-1.540	-46.11
CENTRAL ZONE	36.306	34.387	1.919	5.58
ANDHRA PRADESH	0.600	0.390	0.210	53.85
TELANGANA	9.209	10.070	-0.861	-8.55
KARNATAKA	2.889	1.647	1.242	75.41
TAMILNADU	-	0.003	-0.003	-100.00
SOUTH ZONE	12.698	12.110	0.588	4.86
ODISHA	0.263	0.285	-0.022	-7.72
OTHER	0.260	0.299	-0.039	-13.04
GRAND TOTAL	64.077	61.732	2.345	3.80

SOURCE : MINISTRY OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE

साल-दर-साल दम तोड़ रही यूपी की टेक्सटाइल इंडस्ट्री



हाथरस के कॉटन ट्रेडर श्रवण कुमार अग्रवाल से एसआईएस की खास बातचीत

पूरे देश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा रहा है लेकिन यूपी में साल-दर-साल यह इंडस्ट्री दम तोड़ती जा रही है। कॉटन की पैदावार हो या जिनिंग और स्पिनिंग मिल्स की यूनिट लगाने की बात, यहां स्थिति देश से विपरीत ही है। हाथरस जैसे कॉटन ग्रोइंग स्टेशन में ही हर साल कपास का रकबा लगभग 10 प्रतिशत तक कम होता जा रहा है। वहीं कुछ साल पहले तक कानपुर और हाथरस यूपी के कॉटन हब कहलाते थे जबकि अब यहां एक भी मिल का असतित्व नहीं है। देश के सबसे बड़े स्टेट में देश की दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री का ये दर्श ज़िम्मेदारों के लिए सोचने का विषय है।

महंगी है लेबर कॉस्ट

कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के विषय में यह चिंता व्यक्त की यूपी के हाथरस इलाके के कॉटन ट्रेडर श्रवण कुमार अग्रवाल ने। श्रवण ने बताया कि कॉटन इंडस्ट्री में जबरदस्त स्कोप है लेकिन यूपी में नहीं। दरअसल कपास फसल की कटाई के लिए लेबर की बहुत आवश्यकता होती है और यूपी में लेबर कॉस्ट बहुत महंगी है। इसलिए किसान कपास की जगह मक्का और बाजरा की खेती को तवज्जो दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जिनिंग और स्पिनिंग मिल्स लगाना एक बहुत बड़ा इनवेस्टमेंट होता है जिसके लिए सरकार की तरफ से कोई मदद उपलब्ध नहीं है। यही वजह है कि यूपी में इस इंडस्ट्री का फ्यूचर खतरे में नजर आ रहा है।

सरकार से मदद की आस

उन्होंने कहा कि यूपी बेल्ट का हाथरस इलाका देशी कॉटन की पैदावार के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहां औसतन हर साल 8 से 10 हजार कॉटन बेल्ट्स की प्रेसिंग होती है जबकि पूरे यूपी में लगभग 50 लाख बेल्ट्स के लगभग बेल्ट्स की प्रेसिंग होती है। सरकार चाहे तो इस दम तोड़ती इंडस्ट्री को बचा सकती है। जरूरत है तो केवल कुछ आसान नीतियां बनाने की। ऐसी नीतियां जिससे लेबर कॉस्ट और इंडस्ट्री कॉस्ट को कम करने में मदद मिलें।

नॉर्थ जोन

पिछले साल गुलाबी सुंडी रोग से फसल को जो नुकसान हुआ है उसका भय इस साल भी किसानों में नजर आ रहा है। नतीजा यह कि साल 2021-22 में जून महीने के अंत में 14.651 लाख हेक्टेयर में कपास की बुआई की गई थी जबकि साल 2022-23 में यह केवल 14.550 लाख हेक्टेयर पर ही सिमट गई।

सेंटल जोन

सेंटल जोन में कुल सोइंग में 1.919 लाख हेक्टेयर का इजाफा हुआ है। इसमें मुख्य भूमिका महाराष्ट्र ने निभाई है। साल 2021-22 में इस समय तक सेंटल जोन में कुल सोइंग 34.387 लाख हेक्टेयर हुई थी जबकि साल 2022-23 में 36.306 लाख हेक्टेयर भूमि पर कपास की बुआई की गई है।

साउथ जोन

आंध्रप्रदेश में सोइंग में 0.210 लाख हेक्टेयर का इजाफा हुआ जबकि तेलंगाना में 0.861 लाख हेक्टेयर रकबे की कमी दर्ज की गई। कर्नाटक में 1.242 लाख हेक्टेयर ज्यादा भूमि पर कपास की सोइंग की गई। तमिलनाडू में अब तक सोइंग का श्रीगणेश ही नहीं हुआ है। पिछले साल की तुलना में साउथ जोन में कुल 0.588 लाख हेक्टेयर भूमि का इजाफा हुआ है।

तीनों जोन के अलावा उड़िसा और अन्य राज्यों में भी सोइंग पिछले साल की तुलना में कम ही देखी गई। देश में कुल इस समय तक साल 2021-22 तक 61.732 लाख हेक्टेयर भूमि पर कपास की सोइंग की गई थी जबकि इस साल 64.077 लाख हेक्टेयर भूमि पर कपास बोया गया है। (सभी आंकड़े मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉर्मर्स वेलफेयर द्वारा जारी रिपोर्ट पर आधारित)